'अप्प दीपो भव'

वॉयस ऑफ बुद्धा

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2013-15
WPP Licence No.- U(C)-101/2013-15
R.N.I. No. 68180/98

Date of Publication : 31.01.2015
Date of Posting on concessional rate :
2-3 & 16-17 of each fortnight

मूल्य : पाँच रूपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज (राम राज) चेयरमैन - जस्टिस पब्लिकेशंस, टी-22, अतुल ग्रोव रोड, क्नॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, फोन : 23354841-42

Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com

● वर्ष : 18 ● अंक 5 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● 16 से 31 जनवरी, 2015

उत्तर पश्चिम दिल्ली लोक सभा क्षेत्र में मनाया गया डॉ उदित राज का जन्म दिन

उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा क्षेत्र एवं अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ की दिल्ली इकाई द्वारा माननीय डॉ0 उदित राज का जन्म दिन 26 जनवरी, 2015 को अपरान्ह 1 बजे से 'रिट्रीट, आमंत्रण लॉन, पल्ला मोड़, अलीपुर, दिल्ली में मनाया गया। इसके लिए लगभग 10 दिन पहले से ही डॉ0 उदित राज के सचिव, श्री परमेन्द्र, सीमा कौशिक, प्रीती बहन, डॉ0 प्रीती अग्रवाल, रश्मि घिरिया, अनीता राना, मालती रावत, ज्योति अरोड़ा, मनीषा जैन, रचना, नरेन्द्र कुमार सैनी, कुलदीप यादव, विजय चावरिया, रूपेश, कुमार, विजेन्द्र राणा, अशोक सोलंकी, राज जैन, अन्जुम खां, भगत जी, बबल सोनकर, आशुतोष, राजू, नीरज, राजेन्द्र आदि ने तैयारियां शुरू कर दी थी।

डॉ0 उदित राज का जन्मदिवस दशकों से अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ व अन्य सामाजिक न्याय के लिए कार्य कर रहे संगठनों व व्यक्तियों द्वारा 'जस्टिस डे' के रूप में मनाया जाता रहा है। इस वर्ष परिसंघ की दिल्ली इकाई व उत्तर पश्चिम दिल्ली लोक सभा क्षेत्र के लोगों ने उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपने सांसद डॉ0 उदित राज जी का जन्मदिवस 'जस्टिस डे' के रूप में मनाया। लगभग दो घंटे तक लगातार शुभचिंतकों द्वारा गुलदस्ते भेंट करते हुए जन्म दिन की हार्दिक बधाई देने का सिलसिला चलता रहा। जिसमें उत्तर पश्चिम दिल्ली लोक सभा क्षेत्र के सभी प्रमुख पदाधिकारी व कार्यकर्त्ता और दिल्ली प्रदेश परिसंघ के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। डॉ0 उदित राज अपने वक्तब्य में सभी आगन्तुकों का अभार व्यक्त करते हुए अपने जीवन का साक्ष्य का बयान करते हुए कहा कि सभी लोग अपने लिए जीते हैं और जो जीना भी चहिए परन्तु अपने जीवन का कुछ अंश यदि औरों के लिए लगाया जाए तो उसका फल अलग ही होता है, जो कि मैंने अपने जीवन में चरितार्थ करते हुए अनुभव किया है और उसका अलग ही आनन्द होता है और देश सेवा में समर्पण का भाव महसूस कराता है। जिसे सुनकर उपस्थित सभी महानुभाव उनके जीवन का सार्थ्य और आत्मिक सुख से अवगत हुए और उनमें प्रेरणा जगी कि उन्हें भी अपने जीवन में

(शेष पृष्ठ 6 पर)

जन्मदिवस के अवसर पर डॉ0 उदित राज के बाएं पत्नी सीमाराज, बेटी सावेरी, बेटा अभिराज व अन्य एवं दाएं परमेन्द्र एवं अन्य सहयोगी

बजट में दलित

डॉ. उदित राज

सरकारी नौकरियों एवं राजनीति में आरक्षण आर्थिक उत्थान के लिए मूल रूप से नहीं दिया गया था बल्कि भिन्नता वाले समाज में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और मूल कारण यह भी है कि विभिन्न वर्गों एवं समुदायों का शासन-प्रशासन में प्रतिनिधित्व हो। आज़ाद भारत के पहले यह व्यवस्था नहीं थी और किन हालातों से देश गुजरा हम सभी जानते हैं। दलित-आदिवासी की आबादी 25 प्रतिशत है और स्पष्ट नीति है कि योजनागत बजट में से इसी अनुपात में धनराशि का आबंटन होना चाहिए। भारत सरकार एवं राज्य सरकारों का दायित्व है कि इन वर्गों की रक्षा करें, ताकि इनका भी विकास औरों की तरह हो। इसके बावजूद भी इनका जब विकास नहीं हो रहा था तो सरकार ने सोचा कि कोई और विकल्प तैयार किया जाए। इन परिस्थितियों में योजना आयोग ने केन्द्र एवं राज्य स्तर पर योजनाएं बनायी। 1974-75 में ट्राइबल सब-प्लान (टी.एस.पी.) और सिड्यूल्ड कास्ट सब-प्लान (एस.सी. सी.पी.)1979-1980 में बनाया गया। इसके पीछे सोच यह थी कि इनके विकास के लिए धनराशि को अलग रख दिया जाए। इसके बावजूद भी दलित-आदिवासी का बजट में जो हिस्सा मिलना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है और जो उपलब्ध है भी उसका भी इस्तेमाल ठीक से नहीं किया जाता। कभी संसाधन को दूसरी योजनाओं में लगा दिया जाता है तो कभी खर्च ही नहीं किया जाता और इसे वापिस भी कर दिया जाता है।

यदि हम विश्लेषण करें कि किस तरह से संसाधन का बंटवारा हुआ है तो स्पष्ट हो जाएगा कि भेदभाव हो रहा है। पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं, जैसे- 10वीं, 11वीं एवं 12वीं के अंतिम तीन वर्ष को देखें तो भारी मात्रा में संसाधन में कटौती हुई है। सन् 2002 और 2003 में योजनागत् बजट 71,569.41 करोड़ था और उसमें से मात्र 305.73 एस.सी.एस.पी. एवं टी.एस.पी. के अधीन दिया गया था, जबकि यह राशि 17,462.94 होनी चाहिए थी। 2002 और 2003 में 249.75 था जबकि 19187.68 होना चाहिए था और इसी तरह से लगातार 2007 तक हिस्से में कटौती होती रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना - 2007 एवं 2008 में एस.सी.एस.पी का 13307.80 की कटौती थी और 2008 और 2009 में 15004.50 की राशि की कमी थी। 2013-2014 में कटौती की गयी राशि 26327.89 करोड़ थी।

दलित और आदिवासी न केवल एक कारण की वजह से भेदभाव के शिकार हैं बल्कि कई वजहें हैं। भेदभाव यहीं नहीं समाप्त होता बल्कि आगे और बढ़ जाता है जब इस राशि का उपयोग नहीं होता। 2012 और 2013 में एस.सी.सी. पी. के तहत 37113.03 की राशि आबंटित थी और उसमें से 3952.09 का उपयोग हुआ ही नहीं। भेदभाव एक और स्तर पर होता है और वह है, जब राशि का उपयोग होता है। इस राशि का आबंटन अनुमानित अर्थात् काल्पनिक होता है। तर्क यह दिया जाता है कि मंत्रालय की तमाम स्कीमों का विभाजन नहीं हो पाता अर्थात दलितों व आदिवासियों के विकास की योजना का विभाजन अन्य से नहीं किया जा सकता। तकनीकी स्तर पर इसकी गणना 16.2 प्रतिशत 789 छोटे मदों में दिखा दिया जाता है। यह तकनीकी डाटा आबंटन का मापदंड मान लिया जाता है जबकि जिन तक पहुंचना होता है, वे वंचित रह जाते हैं। सर्व शिक्षा अभियान एवं हेल्थ मिशन में जो

(शेष पृष्ठ 2 पर)

एक ऐतिहासिक विकास क्रम : चांडाल से वाल्मीकि तक का सफर

अर्जुन श्री मंडावली

गांवों और नगरों की साफ सफाई से लेकर घरों की साफ सफाई करने वाले श्रमजीवी समाज को हिन्दू ब्राह्मणिक सामाजिक व्यवस्था में भंगी जाति के नाम से जाना जाता है। भंगी शब्द इतना ज्यादा अपमान जनक शब्द है कि, आज भी बतौर गाली के इस्तेमाल किया जाता है। जब भंगी शब्द इतना अधिक अपमानजनक है, तब भंगी जाति के प्रति कितना अधिक अनादर है, इससे समझा जा सकता है कि भंगी जाति अन्य भी कई नामों से जानी जाती है। यथा–धानुक, डोम, डोमर, हेला, खपच, हांड़ी, मखियार, भूई माली, बंसफोड़, मुसहर आदि। इन सभी का वंशानुगत पेशा साफ–सफाई करना ही हैं। हम इन्हें सफाई–कर्मी समाज भी कह सकते है। आजादी के 67 वर्षो के बाद भी इनकी स्थिति यथास्थिति वाली ही बनी हुई है। अर्थात आजादी के पहले जो इनकी स्थिति थी वह आज भी है। बहुत सी जगहों पर इनकों आज भी होटलों में चाय गिलासों में नहीं देते बल्कि इनके लिए अलग से बर्तन रखतें है। दूर से सामान देते है, कहीं इनसे छू न जाए के भय से अर्थात अपवित्र हो जाने के भय से। कहना ना होगा कि इनके प्रति छुआछूत की भावना अभी भी बरकरार है। सच में सफाई कर्मचारी समाज उत्पीड़न, घृणा शोषण और सरकारी उपेक्षा का आज भी शिकार है। सफाई कर्मचारी समाज जो जीवन जी रहा है। वह अतीत की परिस्थितियों से भी मुक्त नहीं हो सका है, अतः हम उस अतीत को जाने बगैर बदलाव की मंशा नहीं रख सकते हैं। ऐतिहासिक विकास क्रम पर एक नजर डालते हैं। सिन्धु घाटी की सभ्यता की खोज से यह प्रति स्थापित हुआ है कि आर्य बाहर से आए आक्रमणकारी लोग थे। इन आर्यो के प्रमाणिक साहित्य में वेदों का परम महत्व है।

1– युद्ध में पराजित एवं अधिकृत अनार्य दास अथवा शूद्र कहलाए। आर्यो ने इन्हें अपने कार्य में यथा सेवा और आर्थिक कार्यो में नियोजित किया। 2– अपनी व्यवस्था को दैवी स्वरूप देने हेतु आर्यो ने ऋगवेद के पुरुष सुक्त में चार वर्णो की उत्पत्ति ब्रम्हा जी से हुई है, ऐसा लिखा है। जिसमें शूद्रों की उत्पत्ति ब्रम्हा जी के पैरो से हुई है ऐसा उल्लेखित है। इसे ही वर्ण व्यवस्था का नाम दिया गया।

3 – कालान्तर में यह चतुर्वर्णी व्यवस्था जाति व्यवस्था में रूपान्तरित हुई, अतएव शूद्र वर्ण भी बहुत सी जातियों – उपजातियों मे विभक्त हो गया।

4 – आर्यो की वर्ण और जाति व्यवस्था श्रम विभाजन पर आधारित रही है, हां इतना जरूर है, शूद्रों को सभी उपेक्षित और घृणास्पद कार्य ही सौंपे गए। इसके मूल में विजित और विजेता की भावना काम करती नजर आती है।

5– शूद्रों की जातियों मे एक जाति रही है। साफ–सफाई करने वाली सेवादार जाति हम उसी की चर्चा को आगे बढ़ा रहे है। साफ–सफाई का काम करनेवाली जाति का हमें परिभाषा में लिखित बौद्ध साहित्य में चांडालों के रूप में उल्लेख मिलता है। पालि साहित्य में चांडालों का झाड़ना–बुहारना वंशानुगत पेशा बताया गया है। सन् 1020 ई. के लगभग लिखते हुए अल बरुनी ने डोम तथा चांडाल को ऐसे दो समूहों के रूप में साथ – साथ बतलाया जाता है कि वे गांवों की सफाई तथा ऐसे ही गंदे कार्य में लगे रहते हैं।

6– ऐसा लगता है कि अतीत में साफ सफाई का काम चण्डाल, खपच, डोम मुश्टक, पौलाक्कस आदि किया करते थे। मोटे तौर से हिन्दू ब्राह्मणिक सामाजिक व्यवस्था में सफाई कर्मचारी खपच, चांडाल, डोम और रामायण काल में मुश्टक नामों से पहचाना जाता रहा, सभी आर्थिक सामाजिक धार्मिक राजनितिक उपेक्षाओं, वर्जनाओं, उत्पीड़नों और शोषणों के साथ।

7– मुस्लिम शासन काल में इनको नाम मिला मेहतर, खाक, रौब, शेख भंगी, लाल बेगी, मूसली मलकाना और मुगल काल में अकबर बादशाह ने इनको नाम दिया हलाल खोर का। इस दौर में सफाई कर्मचारी सामाज ने मुस्लिम समाज के इस्लामिक रीति रिवाजों को आत्म–सात कर लिया यथा कलमा–पढ़ना नवाज पढ़ना, रोजा रखना, ताजिया रखना, फातिया करना, चालिसी करना आदि।

8– अभी कुछ अंशो में इस्लामिक रीतों – रिवाज सफाई कर्मचारी समाज में बरकरार है। कुछ सफाई कर्मचारी समाज के लोग आज भी पूर्ण रूपेण मुस्लिम ही हैं। उदाहरण स्वरूप मध्यप्रदेश में हेला जो की सफाई कर्मचारी का ही कार्य करते हैं। परन्तु अपने आपको इब्राहिम रोहिला का वंशज घोषित करते हैं।

9– सन् 1880 – 90 के दशक में सफाई कर्मचारी समाज के लोग बड़े पैमाने पर ईसाई धर्म में दीक्षित होने लगे जिससे हिन्दू समाज के चिंतकों के तोते उड़ गए। जिसमे आर्य समाज के एक आर्यसमाजी चिंतक अमीचंद शर्मा जी थे।

10– पंजाब की चूहड़ा (भंगी) जाति के लोग बालाशाह और लालबेग को अपना धर्म गुरु मानते थे। लालबेग और बालाशाह कौन थे? यह कोई नहीं जानता परन्तु लोक कथाओं में लालबेग कहीं लालबेग बन जाते है तो कही बाल्मीकि के बेटे। कुर्सी नामें बाइस में अल्लाह–अल–रहीम से शुरू होते थे और रब्बुल आलमीन बोलो मोमिनो वही एक पर खत्म होते थे। कुर्सी नामा वह प्रार्थना थी जिसे आज के सफाई कर्मचारी समाज के लोग ढाई ईंट के थान के इबादत घर के सामने, अपनी धोती की कांच खोलकर खड़े होकर पढ़ते थे। वह प्रार्थना कुछ इस तरह से थी– हम भंगी सबके संगी, भले बुरे के साथ न जाये। दर – दर मांगे कर–कर खाएं। आकाश झाड़े पाताल झाड़े, सोने की झाड़ू – चांदी का पंजा।

11– लाहौर के खाकशाह महाराज के सुजान सिंह नामक अंग्रेजी सेना के एक सैनिक शिष्य बन गए। जो कि सफाई कर्मचारी समाज से थे। खाकशाह महाराज जी ने ही उन्हें सूजान सिंह को महर्षि बाल्मीकि की रामायण में वर्णित शिक्षाओं से अवगत कराया और सफाई कर्मचारी समाज में महर्षि बाल्मीकि की शिक्षाओं को प्रचारित करने हेतु प्रोत्साहित किया, जिसे सूजान सिंह ने बख्खूबी निभाया।

12– कहते है की बाबा खाकशाह महाराज जी के विचारों से प्रभावित होकर आर्यसमाजी अमीचंद शर्मा सफाई कर्मचारी समाज के बीच काम करने का निश्चय कर सफाई कर्मचारी समाज को महर्षि बाल्मीकि की शिक्षाओं और पंथ से जोड़ने का प्रयास शुरू किया।

13– इस तरह अमीचंद शर्मा सफाई कर्मचारी समाज के बीच आये और सफाई कर्मचारी समाज की तनख्वाह के मुद्दे को लेकर अनशन किया और जेल भी गए थे। तब से सफाई कर्मचारी समाज में उनकी शाख और पहचान बन गई। अमीचंद शर्मा ने बाल्मीकि प्रकाश पुस्तक लिखकर सफाई कर्मचारी समाज के लोगो को बताया कि जिस लालबेग या बाबरीक की पूजा वे करते है। वह असल में रामायण रचियता बाल्मीकि ही थे।

14– अमीचंद शर्मा का प्रचार रंग लाया। पंजाब में चूहड़ा और उत्तर प्रदेश में लाल बेगी सफाई कर्मचारी बड़ी तादात में महर्षि बाल्मीकि को स्वीकार करने लगे। और इस तरह बतौर बाल्मीकि जाति के रूप में परिणित हो गए। कहना न होगा कि बड़े ही सातिराना तरीके से यहां के मूल निवासियों को हिन्दु धर्म और जातीय व्यवस्था में समाहित कर लिया गया।

15 – सन् 1931 में सफाई कर्मचारी समाज को बाल्मीकि जाति एवं हिन्दू धर्म के रूप में सरकारी दस्तावेजों में स्वीकृति मिल गई।

16– सन् 1942 में इलाहबाद में पहली बार सफाई कर्मचारी समाज ने स्व0 बाल्मिकानन्द जी के नेतृत्व में बाल्मीकि जयंती मनाई। इस तरह से चांडाल से बाल्मीकि जाति का सफर पूरा किया सफाई कर्मचारी समाज ने।

+++

बजट में.....

(पृष्ठ 1 का शेष)

राशि शामिल होती है, वह एक तरह से अनुमानित ही होती है और इसमें एस.सी.एस.पी. एवं टी.एस.पी. की अच्छी–खासी राशि होती है और यह भी खानापूर्ति का हिस्सा बन जाती है जबकि ये योजनाएं सभी के लिए हैं। ज्यादातर योजनाएं पुराने जमाने की हैं और जो विकास में असली सहयोगी हैं, जैसे – स्किल डेवलपमेंट, जमीन की खरीद एवं व्यवसायी बनाने पर खर्च किया जाना चाहिए। जब तक यह पैसा व्यक्ति, परिवार एवं बस्ती को सीधे नहीं पहुंचती है तब तक कैसे विकास हो सकता है? 43 मंत्रालय एवं विभाग ऐसे हैं, जिन पर इन योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी ही तय नहीं है। वित्तीय वर्ष 2012–2013 में 6918.09 लक्ष्य केन्द्रित थी जबकि 2292.23 अनुमानित और 12333.99 लक्ष्य रहित थी। औसतन 70 से 75 प्रतिशत राशि लक्ष्य रहित होती है। यदि हम विश्लेषण करें तो पाएंगें कि ज्यादातर खर्च दलित–आदिवासी के जिन्दा रहने पर ही खर्च कर दी जाती है, जो कि 68 प्रतिशत है। विकास पर मात्र 20 प्रतिशत ही खर्च होती है। 2013–2014 में योजनागत बजट की राशि 555322 थी और इन योजनाओं के तहत 41561 करोड़ का ही आबंटन किया गया यह हमेशा आबादी के अनुपात में कम ही पैसा वितरित होता है।

कुछ राज्य भेदभाव करने में माहिर हैं और वे सामान्य योजनाओं में खर्च कर देतेहैं। जैसे उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण पर 40. 51 करोड़ खर्च किया गया। इनके पैसे से जेल बनवायी गयी। सन् 2010 एवं 2011 में दिल्ली में 744 करोड़ रूपये को कॉमन वेल्थ गेम्स में लगा दिया गया। उ0प्र0 अनुमानित आधार पर राशि को खर्च करने में आगे है।

लखनऊ में आईटीआई अलीगंज में कर्मचारियों हेतु प्रशिक्षण केन्द्र बनवाने में 14.41 करोड़ की धनराशि खर्च की गयी। 789 छोटे मदों के सामने एस.सी. सी.पी. एवं टी.एस.पी. की राशि को दर्शाना चाहिए। म0प्र0, महाराष्ट्र एवं राजस्थान में 20 ऐसे विभाग हैं जिन्होंने इनके नाम पर खाता ही नहीं खोला है। कुछ राज्य तो ऐसे हैं, अनुमानित उपयोग के आधार पर खर्च का प्रतिशत निकाल देते है।

दलितों एवं आदिवासियों के लिए इन योजनाओं का नवीनीकरण नहीं के बराबर किया गया है, जिससे पैसा खर्च होने के बाद में भी उत्थान नहीं हो पाता। जिन संस्थाओं के द्वारा इन योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है।

वे असफलता के लिए तमाम कारणों को उद्धत करते हैं और कई स्थानों पर नोडल आफीसर तक भी नहीं नामित किए जाते।

मंत्रालयों में कोई ऐसा प्रकोष्ठ नहीं बना हुआ है, जो यह निगरानी करे कि पैसे का दुरूपयोग नहीं हो रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में सर्व शिक्षा अभियान की निगरानी के लिए 40 लोगों की टीम बनी है, तो इसके लिए कोई ऐसी टीम क्यों नहीं बनायी जा सकती? वित्त मंत्री बजट पेश करने जा रहे हैं और उम्मीद की जाती है कि इन पहलुओं पर ध्यान देगें। सरकार को कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए कि जो इन योजनाओं की अवहेलना करे उनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही हो। जिस तरह से आंध्र प्रदेश की सरकार ने इन योजनाओं को लागू करने के लिए कानून बनाया, उसी तरह से अन्य राज्यों और केन्द्र सरकार को करना चाहिए।

+++

डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर जी के निष्ठावान साथी महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल

न्या. सुरेश घोरपड़े

भारत में हजारों साल पहले से भारत मे सिंधु संस्कृति चलती आई है। उसमें समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा था। उसमें मातृसत्मक, कुटूंब पद्धति थी। वो नागवंशी मूलनिवासी बहुजनों को थी। लेकिन चार हजार साल पहले भारत पर आर्य पंडितों का हमला हुआ। और उन्होंने बरराजा बलिराजा को हराकर बहुजनों को धार्मिक, सांस्कृतिक आर्थिक, शैक्षणिक, मानसिक गुलाम बना दिया। इसके खिलाफ भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, सम्राट अशोक, गुरु बसवेश्वर, गुरु कबीर, गुरु रविदास, गुरु नामदेव, गुरु नानक, गुरु तुकाराम, गुरु गाडगेबाबा, सेना महाराज, सेवालाल महाराज तथा शिवाजी महाराज, जीजामाता, अहिल्यामाता होलकर, ज्योतिबा फुले, छ.शाहू महाराज और डॉ. बाबा साहब आंबेडकर, अण्णाभाउ साठे, शहीद मातादीन वाल्मीकि, इन्होंने वर्णभेद जातिभेद के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। और अपनी इस शताब्दी में डॉ.बाबा साहब आंबेडकर ने सबसे बड़ा संघर्ष समता लाने के लिए किया। उनके इस कार्य के लिए उत्तर भारत, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, कश्मीर, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, आसाम, कर्नाटका, मध्यप्रदेश, ऐसे सभी प्रांतों से बाबा साहब को सहकार्य मिला।

इसी तरह भारत के अविभाजित बंगाल प्रांत से जोगेंद्रनाथ मंडल साहब ये बंगाल के थे। इन्होने बाबासाहब के आंदोलन में अमूल्य योगदान दिया। जोगेंद्रनाथ मंडल साहब का जन्म 29 जनवरी 1904 में बोरीसाल जिले के मोयस्तास्कोडी गांव मे हुआ। उनके पिताजी का नाम रामदयाल मंडल था तथा माता का नाम संध्यादेवी था। उनके तीन भाई और दो बहनें थी। वे मूलनिवासी अनुसूचित जाति के नमोशूद्र जाति के थे। उनके चाचा रामकृष्ण जी ने उन्हें गोद लिया था। वे बचपन मे बहुत होशियार थे। उनकी स्मरणशक्ति अच्छी थी। उनको वर्णभेद तथा जातीयता की बहुत तकलीफ हुई। 1924 में मैट्रीक पास हुए । वे गणित तथा संस्कृत मे होशियार थे। उनके वंशज पहले का बंगाल और आज का बांग्लादेश यहां के थे। उस जमाने में नमो शूद्र जाति बहुसंख्यक थी। आज से एक हजार साल पहले पूरा बंगाल बौद्ध धर्मीय था। बौद्ध होने का मतलब कोई जाति नही है यह एक मानवतावादी विचारधारा है। उस समय काली मंदिर मे अनुसूचित जाति के लोगों को जाने नही देते थे। मंडल साहब ने बताया कि पत्थर की पूजा करने के बजाय शिक्षा लो। 1926 मे वे इण्टर परीक्षा पास हुए। उनका विवाह कमला देवी से हुआ।

1929 में बोरीसाल जिले के ब्रिजमोहन महाविद्यालय से वे बी.ए. पास हुए। उस समय महाराष्ट्र मे डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर ने महाड के चवदार तालाब के पानी के लिए सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया था। 1930 में वे ढाका विश्वविद्यालय मे पढ़ने के लिए गए लेकिन वे वापस कलकत्ता आए और 1934 मे उन्होनें एल.एल.बी.परीक्षा पास की। उस समय उन्होने शिक्षा खर्चा ट्यूशन लेकर तथा प्रेस में काम करके प्राप्त किया। उन्होने समाज के हित के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट मे वकालत शुरु की लेकिन बाद मे वे अपने गृह जिला बोरीसाल के जिला न्यायालय मे वकालत शुरु की। वे गरीबों के वकील थे। वे बहुत बुद्धिमान वकील थे। 1928 में सायमन कमीशन भारत मे आया था। उसके सामने डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति, जनजाति की कैफियत रख दी। 1930-31 मे अंग्रजों ने बुलाये हुए गोलमेज परिषद् के लिए डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर लंदन गये थे। वहां पर बाबा साहब का प्रभावशाली भाषण हुआ। इसलिए वे जगप्रसिद्ध हुए और यह बातें समाचार पत्रों के माध्यम से पूरे भारत में प्रसारित होती थी। उस वक्त 1930 में नासिक के कालाराम मंदिर का आंदोलन बाबासाहब ने शुरु किया था और उसकी जानकारी पूरे भारत में समाचार पत्रों के माध्यम से जनता को मिलती थी। 1932 मे ब्रिटिश सरकार ने बाबा साहब को कम्युनल अवार्ड द्वारा अनुसूचित जाति जमाती के लिए स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र मंजूर किए हुए थे। और 1928 मे बाबा साहब की वजह से नौकरी तथा शिक्षा मे 8 आरक्षण अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए अंग्रेजों ने मंजूर किया था। गांधी जी ने स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र का विरोध किया। और इसीलिए 1932 को बाबा साहब को मजबूरन पुणे करार करना पड़ा।

1936 मे जोगेंद्रनाथ मंडल जिला कौंसिल में सर्वाधिक मतों से चुनकर आए थे। वे बहुत लोकप्रिय थे। 1937 में विधानसभा का भारत में पहली चुनाव हुआ था। उस समय बंगाल विधानसभा के चुनाव मे जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने काँग्रेस उम्मीदवार सरलकुमार दत्त को हरवाकर निर्दलीय उम्मीद्वार के रूप मे चुनकर आए । विधायक होने के बाद उन्होने बंगाल मे अनुसूचित जाति के लोगों को पुलिस भर्ती में प्रवेश देने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव रखा। उस समय नेताजी सुभाषचंद्र बोस उनके दोस्त थे। उस समय उन्होने इंडिपेंडेंट्स शेड्यूल कास्ट पार्टी बनायी थी। उस समय हिंदू महासभा के नेता डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विधायक थे। उस समय बंगाल के मुख्यमंत्री मुस्लिम लीग के नजीमोद्दीन थे। उन्होने जोगेंद्रनाथ मंडल जी को उनके मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया। जोगेंद्रनाथ मंडल साहब कबीरपंथी थे। जोगेंद्रनाथ मंडलजी की वजह से प्रशासन में 20 आरक्षण बंगाल मे मिला इसके वजह से बहुत सारे अधिकारी तथा न्यायाधीश बने। उन्होंने विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप देने का प्रस्ताव रखा। 1937 मे डॉ. बाबा साहब आंबेडकर ने स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन किया। 1942 मे अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्रता देने का विचार शुरू किया। तब बाबासाहब ने अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को नये संविधान में अधिकार देने की बात कही। और इसी लिए 1942 मे डा.बाबा साहब आंबेडकर ने दिल्ली में विराट सभा बुलायी। उसमे बंगाल से जोगेंद्रनाथ मंडल, एम.बी.मलिक और विश्वास थे। उत्तर प्रदेश से तिलकचंद कुरील, मद्रास से एम.सी.राजा, महाराष्ट्र से पी.एन. राजभोज तथा दादासाहब गायकवाड़ आये थे। उस समय जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने डॉ.बाबा साहब आंबेडकर की मुलाकात दिल्ली मे की। बाद मे नागपुर मे 1942 मे डा.बाबासाहब आंबेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। उसके बाद 1943 मे मंडल साहब ने उनकी इंडिपेंडेन्ट्स शेड्यूल कास्ट पार्टी का विलय बाबा साहब के शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में कर दिया था। उस समय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की अध्यक्षता मद्रास के प्रो. एन. शिवराज जी ने की। क्योंकि डा. बाबा साहब आंबेडकर को अंग्रेजों ने भारत के मजदूर मंत्री नियुक्त किया था।

उस समय मंडल जी बंगाल के शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के अध्यक्ष थे। जोगेंद्रनाथ मंडल साहब अलग है और 1978 के मंडल आयोग के अध्यक्ष थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल बिहार के थे। जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने जागरण नामक समाचार पत्र निकाला था। उनके पहले बंगाल के सामाजिक नेता गुरुचंद ठाकुर थे। उन्होने बहुत सामाजिक कार्य किया था। 1943 में मुंबई में सहकारी मंत्रियों की परिषद् हुई थी। उसमे जोगेंद्रनाथ मंडलजी सहकारिता मंत्री थे। उसी समय उस परिषद् मे भारत के मजदूर मंत्री डॉ.बाबा साहब आंबेडकर उपस्थित थे। उसी वक्त मंडल साहब ने बाबा साहब की मुलाकात की थी। उस समय जोगेंद्रनाथ मंडल साहब जी ने पूरे बंगाल प्रांत में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की शाखाएं बनायी थी। हर तरफ नीले झंडे लहरा रहे थे। उस वक्त 1945 में पूना में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की कार्यकारिणी की सभा हुई। मंडल जी पूना जाने के लिए जब आगरा रेलवे स्टेशन पर रेल आई तो रात मे हजारों कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए उनके तथा बाबा साहब के नारे लगा रहे थे। उसमे बहुत सारे मुस्लिम कार्यकर्ता थे। पूना में भी उनका हजारो कार्यकर्ताओं ने जयभीम के नारों के साथ स्वागत किया। उन्होने डॉ. अम्बेडकर स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स का उद्घाटन किया। उसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ती आर. आर. भोले जी ने की थी।

कैबिनेट मिशन के कहने के मुताबिक अंग्रेजो ने भारतीय नेताओं को नया संविधान सभा बनाने को कहा। उस समय 292 सदस्य संविधान सभा में चुनना था। बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में चुने जाने के लिए सरदार पटेल ने विरोध किया था। उस समय कम से कम 5 विधायकों को एक संविधान सदस्य चुनना था और बाबासाहब के राजनैतिक दल की 1946 के चुनाव मे हार हुई थी। उस समय जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने दिल्ली में डॉ. बाबासाहब आंबेडकर से मुलाकात की और उनको बंगाल मे चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया। उस समय जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया और उनको पंजाब तथा उत्तर भारत के कलकत्ता मे रहने वाले कार्यकर्ताओं ने बहुत सहकार्य किया। अनुसूचित जाति के विधायकों पर दबाव बनाया। और उस समय जोगेंद्रनाथ मंडल शेडयूल कास्ट फेडरेशन बोरीसाल, निर्दलीय विधायक नागेंद्रनाथ राय रंगपूर, काँग्रेस विधायक गयानाथ विश्वास तंजोल तथा नारायणचंद बर्मन, काँग्रेस विधायक द्वारकानाथ बरुरी फरिदपूर, काँग्रेस विधायक क्षेत्रीनाथ सिंदा रंगपूर, काँग्रेस विधायक बिरसा मुर्षिदाबाद इन्होंने डॉ. बाबा साहब आंबेडकर को मत दे दिया।

बंगाल के महिला कार्यकर्ताओं ने भी बाबा साहब के चुनाव में सक्रिय सहभाग लिया था । सरदार पटेल ने कहा था कि बाबासाहब अम्बेडकर के लिए संविधान सभा के दरवाजे क्या रोशनदान तक बंद किए थे। बाद में बाबा साहब अम्बेडकर की बुद्धिमत्ता तथा उनकी ताकत को देखकर उन्हें संविधान सभा मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाना पड़ा। उसके पहले नेहरू जी ऑस्ट्रेलिया का संविधान तज्ञ जेनिंग को संविधान बनाने के लिए बुलाने का सोचा था और ऐसा संदेशा उन्होंने उनकी बहन विजयालक्ष्मी पंडित के जरिए से दिया था जो उस समय यूनो की जनरल असेम्बली की अध्यक्ष थी। लेकिन जेनिंग ने कहा की, आपके भारत देश मे डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर जैसा कानून पंडित है, उनको संविधान लिखने के लिए बुलाया। बाद मे बाबा साहब आंबेडकर जी को संविधान लिखने के लिए गांधी जी और नेहरुजी ने कहा। और बाद मे बाबासाहब ने अपने बीमार होने के बावजूद भारत का महान संविधान लिखा जो सबका है। इसीलिए उनको भारत के संविधान का मुख्य शिल्पकार पंडित नेहरुजी ने कहा था। कहा जाता है। 1946 में भारत का हंगामी मंत्रिमंडल बन गया। पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने, सरदार पटेल उपप्रधानमंत्री बन गए और मंडल जी 1946 मे कानूनमंत्री थे। और डॉ. बाबा साहब जी को बाद में 1947 में भारत का कानूनमंत्री बनाया गया। इसी समय में बैरिस्टर जिन्ना की वजह से 1947 मे पाकिस्तान बना। और बै.मोहम्मद अली जिना ने जोगेंद्रनाथ मंडल जी को पाकिस्तान के मंत्रिमंडल मे कानूनमंत्री बनाया।

दिल्ली मे आने के बाद जोगेंद्रनाथ मंडलजी का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया सभी तरफ नीले झंडे दिखाई देते थे और डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर के जयभीम के नारे लग रहे थे। वे मुंबई मे डॉ.बाबा साहब अम्बेडकर से मिलने के लिए गए । 1946 मे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का एक और अधिवेशन नागपुर मे हुआ। उसमे जोगेंद्रनाथ मंडलजी का भव्य स्वागत हुआ। उनका जनता के मन पर अधिराज्य था इसलिये उन्हे जनता ने श्महाप्राण श्यानी की ग्रेट लाईफ का खिताब दिया था। बाद मे 1946 मे कलकत्ता मे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का अधिवेशन हुआ। 1947 में आसाम में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का अधिवेशन हुआ। उन्होंने पूरे बंगाल में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की शाखाएं हर जिले मे बनायी। बाबा साहब अम्बेडकर जी को जोगेंद्रनाथ मंडल आदर्श मानते थे। वे बाबासाहब के अनुयायी थे।

1947 में भारत पाकिस्तान बना। उस भारत पाकिस्तान मे जातीय दंगा शुरू हुआ। बंगाल में अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार हुए। 1950 में जोगेंद्रनाथ मंडलजी ने पाकिस्तान के मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया और वे भारत आ गए। डॉ.बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को लाखो लोगों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। बाद में 6 दिसंबर 1956 को डा.बाबासाहब जी का महापरिनिर्वाण हुआ।

बौद्ध धर्मांतरित लोगों को शौक्षणिक व प्रशासनिक आरक्षण की सुविधायें मिलनी चाहिए इसलिए मंडल जी ने प्रधानमंत्री नेहरु जी को पत्र लिखा था। और डा. बाबा साहब की बनायी हुई रिपब्लीकन पार्टी की घोषणा 1957 को हुई। 1963 मे जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने बंगाल मे रिपब्लिकन पार्टी की शाखाएं बनायी। 1964 मे रिपब्लिकन पार्टी का भूमिहीनों के लिये देशव्यापी सत्याग्रह हुआ था। उस संदर्भ मे मंडल जी ने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी से बातचीत की थी। 1967 के सार्वाधिक चुनाव मे रिपब्लिकन पार्टी की ओर से चुनाव लड़े थे। उस समय हाथी चुनाव चिन्ह था 1952 मे ही डॉ.बाबा साहब आंबेडकर ने निर्वाचन आयोग को मांग कर लिया था। उनको रहने के लिये घर नहीं था वह कलकत्ता में बस गये थे। वह किराये के घर में रहते थे। बाद में उन्हे एक कार्यकर्ता ने रहने के लिये घर दिया था। उनके जीवनी के बारे में डॉ.संजय गजभिये और शीलभद्र बौद्ध जी इन्होने किताबें लिखी है। उस समय रिपब्लिकन पार्टी के लिए घूमते वक्त 5 अक्टूबर 1968 को उनका दुखद निधन हुआ। उनका आंबेडकरी आंदोलन के लिए बहुत बड़ा त्याग है। उनको याद करना हमारी जिम्मेदारी है उनके कार्य के लिए उन्हे आदरांजली।

+++

संवेदनाओं का बेजा सवाल

संवेदनाओं का सवाल केवल धार्मिक-सांप्रदायिक मुद्दों पर हीनिराशा जता रहे हैं : एन के सिंह

हर बात में हमारी संवेदना आहत होने लगी है। किसी ने सोशल मीडिया पर कुछ लिख दिया तो हम आहत संवेदना लिए लाठी लेकर खड़े हो जाते हैं, कोई चित्र बना देता है तो हम अपनी फटी-कटी संवेदना के साथ दंगा करने के भाव में आ जाते हैं। वंदेमातरम् गान पर भी संवेदना आहत होती है। हमारी संवेदनाओं के आहत होने की सीमा धार्मिक-सांप्रदायिक मुद्दों तक ही है। ये संवेदनाएं तब आहत नहीं होती जब गरीबी के कारण हम अपने बच्चे को स्कूल न भेजकर मात्र प्रारंभिक धार्मिक तालीम देकर उसे साइकिल का पंचर जोड़ने वाला बना देते हैं या उसका बचपन छीन कर टोकरी बुनने अथवा चंद पैसों के लिए किसी सेठ-सेठानी के पांव दबाने, ढाबे में बर्तन धोने में लगा देते हैं। सरकारी अस्पताल में डाक्टर के न उपस्थित रहने या दवा न मिलने के कारण जब बच्चा मर जाता है तो भी हमारी संवेदनाएं आहत नहीं होतीं। गांव में स्कूल न होने, राशन विभाग में भ्रष्टाचार होने पर भी हमारी संवेदनाएं अक्षुण्ण रहती हैं। हमारी संवेदनाएं तभी सलामत रहती हैं जब हम सड़कों पर भीख मांगते, नशा करते या अपराधी बनते बच्चों को देखते हैं। जब एक बाबा दुष्कर्म के आरोप में जेल चला जाता है तो हम दूसरे बाबा के यहां खड़े हो जाते हैं। संवेदनाएं तब भी तर्क का साथ नही देती।

क्यों पूरा समाज हमारी संवेदना के आहत होने के भाव का खामियाजा भुगते और युवा पौध के बड़े वर्ग को अज्ञानता के अंधकार में रखते हुए मात्र साइकिल का पंचर जोड़ने वाला बना रहने दे। कोई अपने बच्चे को वेदपाठी बनाकर समझता है कि सनातन धर्म का भला कर रहा है तो कोई मात्र कुरान शरीफ की कुछ आयतें रटा कर इस्लाम को मजबूत करने का दंभ भरता है। क्या आज जरूरी नहीं है कि धर्म के नाम पर चल रही दुकानें बंद कराकर समाज को एक नई आधुनिक सोच वाला बनाया जाए जहां गरीबी न हो, अशिक्षा जनित धमर्ंधता न हो और जहां आंदोलन हो तो धर्म या जाति के आधार पर नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ। अब एक और पहलू देखें। पश्चिमी समाज से आयातित महिला विमुक्तिकरण की अवधारणा के तहत हम इस बात के लिए तो यह कहते हुए सड़कों पर आ जाते हैं कि नारी कम कपड़े पहने तो परंपरावादी वर्ग के पेट में दर्द क्यों, लेकिन वही

एनके सिंह, वरिष्ठ पत्रकार

> क्या आज जरुरी नही कि धर्म के नाम पर चल रही दुकानें बंद कराकर समाज को नई सोच वाला बनाया जाए

नारी परिवारों में समान अधिकार के तहत स्कूल जाए और जन्म से पहले भ्रूण के रूप में न मारी जाए, इसके लिए आधुनिकतावादी कोई आंदोलन नहीं करते।

कोई पांच साल पहले बिहार के छपरा जिले के एक गांव के दलितों ने अपने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने से इंकार करते हुए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को भगा दिया। उनकी मांग थी कि पहले बाजार जाने वाली सड़क बनवाओ। छपरा उन दिनों विश्व पोलियो अभियान की सुर्ख़ियों में था, क्योंकि उस जिले में पोलियो देश में सर्वाधिक था।

संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए व शिक्षा और संस्कृति बनाए रखने के लिए सामूहिक अधिकार के रूप में और साथ ही अल्पसंख्यक समूहों के अधिकार के रूप में तीन अनुच्छेद दिए गए हैं। अनुच्छेद 28(1) के अनुसार पूर्णतः सरकारी फंड से संचालित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन अनुच्छेद 28(2) कहता है कि ऊपर का अनुच्छेद 28(1) नहीं लागू होगा यदि वह संस्था किसी ऐसे ट्रस्ट या एंडोवमेंट के तहत जो धार्मिक शिक्षा देने की मंशा से है, स्थापित की गई है, भले ही वह संस्था राज्य द्वारा प्रशासित हो। वहीं अनुच्छेद 28;1द्ध बताता है कि ऐसी किसी भी शिक्षण संस्था के, जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हो या जो राज्य के फंड से चल रही हो, किसी धार्मिक निर्देश में शामिल होना या किसी भी धार्मिक पूजा में उपस्थित होने की अनिवार्यता ऐसे व्यक्ति को नहीं है जो उस संस्था में उपस्थित होता है, लेकिन साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर वह व्यक्ति अवयस्क है तो उसके अभिभावक की अनुमति जरुरी होगी। मतलब यह कि बच्चा आधुनिक शिक्षा ले या मदरसा में धार्मिक शिक्षा ले, यह अभिभावक पर निर्भर है। अगर वह अभिभावक बच्चे को साइकिल का पंचर लगाने के लिए छोड़ दे, उसे सड़कों पर भीख मांगने के लिए छोड़ दे और उसे भविष्य का अपराधी बनाने की स्थितियां पैदा करे तो समाज या संविधान कुछ भी नहीं कर सकता। अगर कोई कानून बनाया जाता है तो उसे धार्मिक भावनाओं से छेड़छाड़ मानकर बवेला मचाया जा सकता है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने ऐलान किया कि लड़कियां स्कूल नहीं जाएंगी। दूसरा फरमान था पुरुष डाक्टर महिलाओं के शरीर को नहीं छू सकता। अब चूंकि लड़कियां पढ़ेंगी नहीं, पुरुष डक्टर महिला शरीर को हाथ नहीं लगाएगा लिहाजा पूरा फाटा क्षेत्र व उत्तरी और पश्चिमी वजीरिस्तान में महिलाएं आधुनिक इलाज और सर्जरी के अभाव में मरती रहेंगी। यह सब तालिबान धर्म के अलम्बरदार के रूप में कर रहा है। उधर पश्चिमी उदारवाद से प्रभावित होकर पिछले साल भारत में एक कानून पास किया गया जिसके तहत कोई बच्चा अपने मां-बाप के खिलाफ मुकदमा कर सकता है कि वह प्रताड़ित किया जा रहा है। यानी अगर मां-बाप बच्चे को पढ़ने के लिए एक चांटा मार देते हैं तो उन्हें जेल हो सकती है। विरोधाभास देखिए कि एक अभिभावक पोलियो ड्राप न पिलाकर बच्चे की जिंदगी पंगु कर सकता है और एक अन्य उसको तथाकथित धार्मिक शिक्षा देकर आधुनिक, रोजगारपरक एवं तार्किक-वैज्ञानिक शिक्षा से वंचित कर सकता है वहीं दूसरा अपने बच्चे को डांट भी नहीं सकता। राष्ट्र के चरित्र में एक अजीब विरोधाभास दिखाई देता है। ताजिया किधर से निकले या रामलीला कहां हो, इस बात पर दंगा, धर्म कैसे बदला इस बात पर दंगा, लेकिन एक भी आंदोलन इस बात पर नहीं कि गरीब बस्तियों में पानी क्यों नहीं, उनके बच्चों को भी वही शिक्षा क्यों नहीं, टीकाकरण से लेकर इलाज के लिए अस्पताल अल्पसंख्यक इलाकों में कम क्यों। क्यों अल्पसंख्यक और दलित ही आज भी गरीब हैं और क्यों कानून लाकर उनके बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य नहीं किया जा रहा है?

साभार - दैनिक जागरण

+++

उ0प्र0 परिसंघ की इकाई भंग

गत् कई वर्षों से अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ की उ0प्र0 इकाई में शिथिलता आ चुकी थी। कुछ जिला इकाइयां पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुकी थीं। गत् कई रैलियों में न के बराबर सहयोग मिल रहा है, जबकि तमाम संकट से समाज गुजर रहा है।

4 जनवरी, 2011 को लखनऊ हाई कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ निर्णय दिया और यह ऐसा अवसर था कि एक आंदोलन खड़ा किया जा सकता था। इस अवसर का फायदा दूसरों ने उठाया लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। समय, संसाधन का दुरुपयोग कुछ लोग रैलियों एवं सभाओं के माध्यम से किए परन्तु परिणाम शून्य रहा। एक तरह से देखा जाए तो इन्होंने उतना ही नुकसान किया है, जितना हाई कोर्ट ने। इन्होंने लोगों को गुमराह किया, जिससे परिसंघ की शक्ति छीड़ हुई है। यदि परिसंघ की शक्ति छीड़ न होती तो पदोन्नति में आरक्षण की लड़ाई परिणाम तक ले जाती। अब उन गुमराहों को भी पुनर्गठन में जिम्मेदारी दी जाएगी। पुनर्गठन के लिए निम्नलिखित लोगों से सम्पर्क कर सकते हैं -

इनके अतिरिक्त और

जगजीवन - 9415007459
धर्म सिंह - 9415585545
केदार नाथ - 9568677815

लोग भी पुनर्गठन में सहभागिता ले सकते हैं। इच्छुक लोग सम्पर्क करके अपना भी नाम अगले अंक में छपवा सकते हैं। विभिन्न प्रदेशों के इंजार्च जो दिल्ली में नियुक्त किए गए हैं, उनका भी नाम व नम्बर दिए जा रहे हैं। अतः परिसंघ के कार्यकर्त्ता व नेता उनसे सम्पर्क कर सकते हैं। +++

विभिन्न प्रदेशों के प्रभारी

नाम व मोबाइन नंम्बर	प्रदेश
नाहर सिंह - 9312255381	आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु
रविन्दर सिंह -7503051123	उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल
धनंजय सिंह -	दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र
योगेश आनंद - 9654144068 व आर0 एस हंस - 9811800137	मध्य प्रदेश, छतीसगढ़
बलबीर सिंह - 9999051041	गुजरात, राजस्थान, जम्मू काश्मीर
भानू पुनिया - 9013332151	पंजाब, हरियाणा, हिमांचल प्रदेश

पाठकों से अपील

'वॉयस ऑफ बुद्धा' के सभी पाठकों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक वार्षिक शुल्क/शुल्क जमा नहीं किया है, वे शीघ्र ही बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के नाम से टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 को भेजें। शुल्क 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के खाता संख्या 0636000102165381 जो पंजाब नेशनल बैंक की जनपथ ब्रांच में है, सीधे जमा किया जा सकता है। जमा कराने के तुरंत बाद इसकी सूचना ईमेल, दूरभाष या पत्र द्वारा दें। कृपया 'वॉयस ऑफ बुद्धा' के नाम ड्राफ्ट या पैसा न भेजें और मनीआर्डर द्वारा भी शुल्क न भेजें। जिन लोगों के पास 'वॉयस ऑफ बुद्धा' नहीं पहुंच रहा है, वे सदस्यता संख्या सहित लिखें और संबंधित डाकघर से भी सम्पर्क करें। आर्थिक स्थिति दयनीय है, अतः इस आंदोलन को सहयोग देने के लिए खुलकर दान या चंदा दें।

सहयोग राशि:

पांच वर्ष : 600 रुपए
एक वर्ष : 150 रुपए

डॉ0 उदित राज जी के जीवन की एक घटना

सी. एल. मौर्य

माननीय उदितराज का जन्म जनपद इलाहाबाद के गांव राम नगर में हुआ था। इनके पिताजी फौज में थे और माता घरेलू कामकाजी। पिताजी सेवानिवृत्ति के पहले ही नौकरी से इस्तीफा देकर व्यवसाय एवं खेती का काम करने लगे। खेत ज्यादा न होने के कारण व्यवसाय करना जरूरी था। माननीय उदित राज बचपन से ही बड़े न्यायप्रिय स्वभाव के थे और न्याय के लिए मां-बाप से भी तर्क और बहस करने से नहीं चूकते थे। उनके बाल्यकाल को असाधारण रूप से लोग देखते थे, क्योंकि ये मनुवादियों के उन बच्चों से झगड़ा करते थे, जो अन्य गरीब और दलित बच्चों को सताया करते थे। इस बात के लिए इनसे घर वाले भी बड़े नाराज हुआ करते थे कि बिना वजह दूसरे लड़कों से क्यों मार-पीट करते थे ?उस अतीत को समझने के लिए वर्तमान का सहारा लिया जा सकता है। आज वे इतनी बड़ी नौकरी को लात मारकर न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर से यही प्रवृत्ति चेतन या अचेतन अवस्था में बचपन में कार्य कर रही थी। कक्षा दस के बाद विवेक का विकास होने पर भूत-पिचास, कर्मकाण्ड एवं देवी-देवताओं की पूजा के बहुत ही विरूद्ध हुआ करते थे और इस बात के लिए लोग इनके मां-बाप को भी सुनाते थे कि आपका बच्चा किस प्रवृत्ति का है। उदित राज जी के भी घर में अंधविश्वासी लोगों और तांत्रिकों का डेरा जमा हुआ करता था और उनके विरूद्ध नित बगावत करके उस जमावड़े का ये सफाया कर दिया करते थे। ब्राह्मण कथा कराने आता था, उसको भी इन्होंने कुछ परोक्ष या प्रत्यक्ष व्यवहारों से आना बंद कर दिया।

बचपन में जो काम ये कर जाते थे, वह बड़ा ही असाधारण हुआ करता था। अपने भाई कालीचरण के साथ मिलकर एक बार तीन कमरों का मिट्टी का मकान ही बना डाला। पिताजी की सेहत ठीक न होने के कारण खेती के काम में पूरी शिरकत किया करते थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि हाईस्कूल करने के पहले घर की तमाम जिम्मेदारियों में हाथ बंटाने लगे थे। वैसे बचपन से ही बड़ों से तर्क और बहस में हिस्सा लेना जैसे विशेष रूचि रही है। सामान्यतया बच्चों को भारतीय समाज में बड़ों से तर्क और बहस करना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि इसे बड़ों का अपमान समझा जाता है। इसको माननीय उदित राज ने कभी नहीं स्वीकारा।

शायद ही वे बचपन में किसी को अपना आदर्श मानते थे। इसका आशय यह नहीं है कि वे महापुरुषों का अनादर करते थे, बल्कि चेतन या अचेतन अवस्था में यह सोचा करते थे कि वे क्यों नहीं वैसा बन सकते ?कहा जा सकता है कि किसी भी महापुरुष की अच्छी बातें, परोक्ष रूप से प्रेरणा का स्रोत अवश्य हुआ करती रही होगीं। वे अपना फैसला शुरू से ही खुद ले लिया करते थे और गलत होने पर उसमें सुधार भी करते थे। सन् 1978 में अपने साथी के लिए तथाकथित सवर्ण ठाकुरों से बड़ा मोर्चा लिया। हुआ यह था कि इनका मित्र लल्ला कुमार अहिरवार कॉलेज के किसी ब्राह्मण छात्र को चप्पल से मार दिया, तो इस घटना को दो छात्रों की बीच की घटना न मानते हुए यह दुष्प्रचार किया गया कि एक चमार ने ब्राह्मण को चप्पल से मार दिया। इस घटना ने जातीय रूप ले लिया। फिर क्या था, उदित राज (उस समय राम राज) जी को न्याय का मुद्दा ही मिल गया। उन्होंने कहा जब ब्राह्मण छात्र दलित छात्र को मारता है, तब तो यह नहीं कहा जाता कि ब्राह्मण छात्र ने दलित छात्र के साथ ऐसा किया, तो इस मामले को क्यों ऐसा तूल दिया जा रहा है। धीरे-धीरे पूरा माहौल उदित राज जी के खिलाफ ही हो गया। लोगों ने इनको समझाया कि आप क्यों दूसरों के बीच पड़ रहे हैं ?फिर भी ये नहीं माने। याद रहे कि उस समय ये किसी विशेष विचारधारा से प्रभावित नहीं थे। इस समस्या को सुलझाने के लिए इन्होंने दलित एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों को इकट्ठा किया और यह तय किया गया कि छात्रावास से कॉलेज के परिसर में पूरा ग्रुप जाएगा, न कि कोई अकेला, क्योंकि यह अंदेशा था कि तथाकथित सवर्ण छात्र भारी संख्या में इकट्ठा होकर प्रहार करेगें। इन्हीं के समूह से एक छात्र छुपकर कॉलेज परिसर में पहुंच गया, इसलिए कि वह इस झगड़े से दूर रहे, नहीं तो उसे भी सवर्ण छात्र मार सकते थे। इस छात्र के साथ लड़ाई-झगड़े से निबटने के लिए आवश्यक सामान भी थे, लेकिन वह धोखा देकर पहले ही चला गया। चूंकि यह छात्र भी उनकी जानकारी में था, इसलिए जैसे ही कॉलेज के ग्राउंड में पहुंचा सवर्ण छात्रों ने पकड़ लिया और छात्रावास में इसकी खबर भी भिजवा दी। जैसे ही इस घटना की जानकारी माननीय उदित राज को मिली, वे अपने साथी की गद्दारी से दुखी तो हुए, लेकिन उसे छुड़ाने के लिए कॉलेज की ओर चल पड़े। जिस मित्र के लिए यह सबकुछ हो रहा था, वह थाने में रिपोर्ट लिखवाने गया था। उदित राज जी का एक और अभिन्न मित्र पिछड़े वर्ग का हुआ करता था, जिसका अच्छा दबदबा कॉलेज में हुआ करता था। इन्होंने उसे कह दिया था कि वह सुबह ही छात्रावास पहुंच जाए और तभी सब लोग एक साथ कॉलेज के परिसर में

जे.एन.यू. में अध्ययन के समय का डॉ0 उदित राज का फोटो

जाएंगें। यह दोस्त भी जान-बूझकर समय पर नहीं पहुंचा। जब ये कॉलेज की ओर अग्रसित हुए, तो लोगों ने इन्हें रोका, लेकिन इन्होंने कहा कि भले ही साथी गद्दार निकला लेकिन यदि वह पिट जाता है, तो यह मेरे नेतृत्व का अपमान है। अपने भाई एवं कुछ और साथियों के साथ उसे छुड़ाने के जिए चल पड़े और जैसे ही कॉलेज के गेट पर पहुंचे सैकड़ों लोग मार-पीट करने के लिए इंतजार कर रहे थे। यह देख उदित राज जी चौकन्ना तो हुए किन्तु अवसर पाकर एक विरोधी छात्र ने लात से मारने की कोशिश की। तेज नज़र रखने वाले उदित राज जी ने इसका लात ही उठा दिया, जिससे वह गिर गया। इतने में ये घिर गए। दो चार को मार-पीटकर भीड़ को छांटने की कोशिश की, लेकिन एक के बाद एक हमला करने के लिए बढ़ता ही गया। इनके भाई के पास पिताजी की फौज की बेल्ट थी, जो बहुत ही वजनदार थी, जबर्दस्त रूप से इस्तेमाल किया, जिससे भीड़ तितर-वितर हुई। इनकी तरफ मात्र 5-6 लोग थे, जो तमाम लोगों से घिरे थे। भाई की कनपटी पर चोट आई। देखते-देखते पूरे कॉलेज का माहौल गरम हो गया। फिर क्या था, माननीय उदित राज छात्रावास के अधीक्षक, प्रधानाचार्य और तमाम विरोधियों को डांटना-फटकारना शुरू किए कि यह घटना उनकी साजिश से हुई है। इन्होंने कॉलेज का छुट्टी वाला घंटा बजा दिया, जिससे पूरे कॉलेज के छात्र कक्षों से बाहर निकल आए। प्रधानाचार्य को बुरा-भला भी खूब कहा गया। उक्त घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। धीरे-धीरे यह घटना पूरे जिले और उसके बाहर तक फैल गई।

दलित और पिछड़े वर्ग के स्थानीय नेता जो पहले उदित राज जी को लड़ने के लिए प्रेरित करते थे, सब गायब हो गए। गांव में परिस्थिति मजबूत तो थी, लेकिन कॉलेज 5 किलोमीटर दूर होने के कारण वहां तक कोई मदद पहुंचाना संभव नहीं था, अतः जो भी कुछ सहयोग संभव था वह कॉलेज के कस्बे सिरसा एवं आसपास के ही गांव से। घटना के पहले तमाम दलित एवं पिछड़े वर्ग की सभाएं हुआ करती थी, लेकिन इस समय वे नेता काम न आए तो सी.पी.एम. के नेता हरीराम पाण्डेय छात्रावास में मिलने आए। पहले तो उदित राज जी उनसे मिलने से मना कर दिए किन्तु बाद में लोगों के कहने से मिले, तो उन्हें लगा कि यह व्यक्ति मदद कर सकता है। हरी राम पाण्डेय जी ने रिपोर्ट दर्ज करवाने से लेकर अन्य प्रकार की भी मदद की। जिससे माननीय उदित राज सी.पी.एम. से जुड़ गए। सवर्ण छात्रों के विरूद्ध मुकदमें दर्ज हुए। छात्रावास के अधीक्षक को भी घटना में शामिल किया गया। इस बहादुरी के कारण उदित राज जी का दबदबा कॉलेज में बढ़ गया। उनकी प्रवृत्ति यह है कि किसी भी घटना या समस्या से समझौता नहीं करते, बल्कि तीखी प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे इन्हें हमेशा प्रसिद्धि और ताकत मिलती गई। कॉलेज के तमाम मनुवादी मानसिकता के अध्यापक एवं प्रधानाचार्य उस दिन का इंतजार करने लगे, जिस दिन उदित राज पास होकर कॉलेज छोड़ दें। झगड़े के कारण बारहवीं की परीक्षा में इनके नम्बर तो अच्छे नहीं रहे, लेकिन पास हो गए। प्रधानाचार्य को बहुत ही राहत महसूस हुई। बी.ए. में प्रवेश के लिए आस-पास के लोग कहने लगे कि इन्हें स्थानीय डिग्री कॉलेज में ही प्रवेश लेना चाहिए, तो इन्होंने मना कर दिया और कहा कि इलाहाबाद विश्व विद्यालय में ही पढ़ेगें। बी.ए. में प्रवेश के लिए चरित्र प्रमाण-पत्र दाखिल करना जरूरी होता है। दुर्भाग्यवश प्रधानाचार्य ने खराब चरित्र प्रमाण-पत्र जारी किया, जिससे कहीं भी प्रवेश लेना असंभव हो गया। प्रधानाचार्य भी एक पाण्डेय ही थे। अब इनकी लड़ाई अच्छे चरित्र प्रामण-पत्र के लिए जारी होती है। बड़े संघर्षो के कारण अच्छा चरित्र प्रमाण-पत्र जारी हो सका।

उस समय के ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय राज शर्मा, जो दिल्ली के पुलिस आयुक्त रहे हैं, ने इन्हें समझाने की कोशिश की कि ये मुकदमा वापिस ले लें, मगर उदित राज जी ऐसा करने से इनकार कर दिए। मुकदमा खतरनाक किस्म का था, क्योंकि हरीराम पाण्डेय जी के सहयोग से मामला अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज हुआ था।

इसके बाद इलाहबाद विश्वविद्यालय में सी.पी.एम. के छात्र मोर्चा ''स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया'' में सक्रिय हो गए। ये इतने सक्रिय हुए कि पढ़ाई-लिखाई के लिए समय ही नहीं रहता था। उस समय जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र यूनियन के अध्यक्ष देवी प्रसाद त्रिपाठी के नाम की धूम मची थी। त्रिपाठी जी इलाहाबाद से निकले और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र संघ के अध्यक्ष बने और विदेशों में भी अपनी प्रसिद्धि प्राप्त की, जिससे उदित राज जी को लगने लगा कि जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय कोई खास चीज है। अपनी बी.ए. बिना पूरा किए ही जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में पांच वर्षीय एम.ए. की डिग्री के लिए इन्होंने जर्मन भाषा में प्रवेश लिया। यहां भी छात्र राजनीति में सक्रिय होने के कारण स्कूली पढ़ाई करने में पीछे ही रहे। घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण इन्हें लगा कि नौकरी करना जरूरी हो गया है। ये कभी नौकरी के लिए इच्छुक नहीं थे। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के गंगा छात्रावास में रहते थे और इनके साथियों ने इनका फार्म आई.ए.एस. की प्रतिस्पर्धा के लिए भरवा दिया। नौकरी करना मजबूरी हो गई थी, इसलिए इन्हें पढ़ना ही पड़ा और अंत में सन् 1988 में भारतीय राजस्व सेवा में चुन लिए गए।

भारतीय राजस्व सेवा में रहते हुए भी हमेशा इनका दिल वंचितों के लिए ही धड़कता था। जब भी कहीं गरीबों व दलितों के अपमान की बात सामने आती तो इनका खून खौल उठता था। सेवा में रहते हुए इन्होंने आयकर विभाग में एसोसिएशन गठित की। सन् 1997 में तत्कालीन तथाकथित सामाजिक न्याय की सरकार द्वारा जब पांच आरक्षण विरोधी आदेश जारी किए गए तो इनसे रहा नहीं गया और इन्होंने अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ का गठन करके आंदोलन शुरू कर दिया। एक बार जब यह आंदोलन शुरू हुआ तो थमने का नाम नहीं लिया और केन्द्र सरकार को इस आंदोलन के दबाव में संविधान में संशोधन करना पड़ा और काफी हद तक आरक्षण बचा। इन्होंने जब देखा कि सामाजिक आंदोलन की अपनी सीमाएं हैं और दलितों के अधिकार राजनैतिक ताकत प्राप्त करके ही सुनिश्चित कराए जा सकते है। 2002 में सरकारी सेवा से त्यागपत्र देकर आंदोलन के साथियों की सलाह पर इन्होंने इंडियन जस्टिस पार्टी की स्थापना की। 2014 में साथियों सहित भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और 2014 के आम चुनावों में उत्तर पश्चिम दिल्ली से जीतकर लोक सभा में पहुंचे।

उपरोक्त घटना का उल्लेख उनके जन्म दिवस पर करना सार्थक लगता है। यह घटना निश्चित तौर से युवाओं के लिए प्रेरणादायी होगी।

+++

The business of honesty

It's corporations rather than government that can really help fight corruption

Kaushik Basu and Avinash Dixit

Control of corruption is commonly treated as the responsibility of government. The presumption is that people, firms and corporations will be what they are. So if corruption flourishes in a country, it reflects a failure of government. Public outrage against corruption is understandable for corruption is among the biggest obstacles to economic development. At the same time, the solutions offered in popular discourses are often naïve.

We argue here that there is scope for private firms and corporations to develop self-enforcing norms for controlling corruption, in somewhat the same way that people in private housing communities often develop mechanisms for keeping their public spaces clean. There is a fundamental flaw in the popular expectation that government will have an interest in controlling corruption. Most agents who comprise government — politicians, bureaucrats, law enforcement officers — benefit from corruption. Therefore laws are watered down and leave loopholes; enforcement of anti-corruption measures by one branch is obstructed by others. The business community as a whole has stronger incentives to counter corruption. There are situations where business and government can conspire to benefit at the expense of the broader citizenry. But in most contexts involving award of scarce resources such as land, spectrum channels, licences and contracts, politicians' and bureaucrats' gain is the business community's aggregate loss. The winning firm profits, but the efforts and expenses of all the losers more than offset this gain. Worse, to the extent that corruption acts like a tax and therefore deters future investment, it hurts profits and growth for all business.

Thus business as a whole can benefit from the reduction of corruption. Moreover, the cleaning up of corruption can have long-run effects such as those of fostering growth and speeding up development and, as such, it can confer huge benefits to the citizenry.

The trouble is that each firm has an incentive to cheat on any agreement not to bribe. Of course when all firms do this, they collectively lose. This is a prisoner's dilemma game among them, and needs their own collective action: an effective system of norms and sanctions to deter cheating.

Successful community institutions for collective action have existed for at least a millennium. Stanford economic historian Avner Greif analysed a community of Jewish traders in north Africa in the 11th century that sustained honest contracting in long-distance trade among its members through a system of norms and punishments.

University of California economist James Rauch, Chicago Law School professor Lisa Bernstein, and others have studied more recent ethnic networks of traders. India can learn from these examples to set down some features that an anti-corruption business institution should have. Most importantly, the community needs an efficient method to detect and punish cheating. We believe India is fortunate in the first aspect. National and local business associations form good networks, with good communication both formal and informal (gossip), ensuring that insiders quickly come to know any incidents of bribery. India also has high-quality investigative journalists who can provide an additional channel for detection.

The facts may be difficult to prove in a court of law, but this is where an internal tribunal has an advantage: it can use broader standards of evidence, and has insider expertise to evaluate the evidence. As for punishment, the community can deploy even more effective sanctions than the fines a court of law would impose: it can ostracise offenders, basically driving them out of business. Of course such a potent weapon must be used with care; the process needs to guard against false accusations and must ensure that it does not become an insiders' cartel that keeps out new or disruptive entry.

Next, the institution needs large and prominent 'launch members'.

This might often be difficult because existing business leaders may have come to that position by benefitting from the existing corrupt system. But again we believe India is fortunate. In the last two decades many prominent firms and business people have emerged using good governance and operating in the world economy. If they step up to start an institution, inviting others to join in a no-bribery pledge, they can succeed because others will find it a matter of shame to stay out. Government can provide some minimal help by requiring as a condition for a firm to be on its list of approved vendors or bidders that it be a signed-up member of the no-bribery group. One of us (Dixit) has constructed a game-theoretic model, and examined evidence from other business community governance institutions, to list several other desiderata for an anti-corruption institution. We believe they provide the basis for serious public discussion of the idea, and even some experimental implementation in the near future. We hope this essay will help start the process.

We do not offer this as a magic solution that will eliminate all corruption. It is far from being a panacea, but there are no panaceas in life. We believe that this proposal can reduce corruption substantially. It would be a mistake to dismiss it summarily or argue that we should wait for a more perfect solution. Waiting for 100% success merely ensures 0% success. Kaushik Basu is Chief Economist of the World Bank. Avinash Dixit is Professor Emeritus at Princeton University. +++

(Courtesy By - The Times of India)

उत्तर पश्चिम दिल्ली लोक सभा क्षेत्र में .....

(पृष्ठ 1 का शेष)

ऐसा कुछ करना चाहिए।

डॉ0 उदित राज जी का मानना है कि ज्यादातर लोग सफलता प्राप्त लोगों की ओर देखते हैं और उनसे मदद की उम्मीद करते हैं, लेकिन उनका मानना है कि आपके अंदर भी वह ऊर्जा और सामर्थ्य है, जिससे आप भी सफल हो सकते हैं, बशर्ते उसे पहचानने और अमल में लाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यदि सही दिशा में कोई प्रयास करे तो हर व्यक्ति शीर्ष पर पहुंच सकता है। वे हमेशा गरीबों, दलितों व दबे-कुचलों के बारे में ही सोचते रहते हैं कि कैसे इनका कल्याण हो सकता है।

अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ द्वारा इन वर्गों के उत्थान के लिए बहुत कुछ किया जा चुका है लेकिन वह सब अभी होना बाकी है, जो वे वास्तव में करना चाहते हैं।

दलित वर्ग में पैदा बालक के मन में बचपन से ही यह बात बैठा दी जाती है कि अच्छी पढ़ाई-लिखाई करो ताकि एक नौकरी मिल जाए। वे मानते हैं पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जो रोजगारोन्मुखी हो। केवल एम.ए., बी.ए. की डिग्रियां लेने का कोई औचित्य नहीं है।

+++

डॉ. उदित राज के दाएं उनकी पत्नी श्रीमती सीमा राज व साथ में खड़ी सीमा कौशिक, प्रीती बहन, अनीता राना, मालती रावत, ज्योति अरोड़ा, मनीषा जैन, रचना आदि

वट्सऐप पर जुड़े
99 99 50 44 77

साथियो,

वैसे तो हमारे देश में बहुत नेता हैं परन्तु कुछ नेता ऐसे भी हैं जो सरकारी पैसा खर्च कर के सत्तर किलो का केक कटवाते हैं और नोटों एवं हीरों की माला बदवाते हैं । एक युवा नेता ऐसे भी हैं जो टू-जी स्पेक्ट्रम और कोचला घोटाले के पैसों को विदेशों में उड़ाना ही अपना जन्म दिन मानते हैं । लेकिन मैं अपने जन्म दिन पर आप लोगों के लिए एक हाई-टेक तोहफ़ा लाया हूँ । मैं आप सब के लिए एक बहुत ही लाभप्रद एवं समयोपयोगी योजना ले कर आया हूँ । अब आप मुझसे अपनी किसी भी समस्या के समाधान के लिए किसी भी समय जुड़ सकते हैं । मैं आपको अपने जन्मदिन के तोहफ़े के रूप में एक वट्सऐप नं. 99 99 50 44 77 दे रहा हूँ जिसके तहत आप मुझे कोई भी समस्या भेज सकते हैं और उस समस्या पर मेरे द्वारा क्या कार्यवाही की गई है इसका जवाब मिल जाएगा ।

India will succeed if it is not splintered along religious lines of religion

Excerpts from US Presidents Barack Obama speech at Siri Fort, New Delhi on Jan. 27

Our nations are strongest when we see that we are all god's children, that we are equal in his eyes and worthy of his love. Across our two great countries, we have Hindus and Muslims and Christians, and Sikhs and Jews and Buddhists and so many faiths. And we remember the wisdom of Gandhiji, who said, "For me the different religions are beautiful flowers from the same garden, for they are branches of the same majestic tree." Our freedom of religion is written into our founding documents. It is part of America's very First Amendment. Your Article 25 says that all people are equally entitled to freedom of conscience and the right to freely profess and propagate religion. In both our countries — in all countries — upholding this fundamental freedom is the responsibility of government. But it is also the responsibility of every person. In our life, Michelle and I have been strengthened by our faith. But there have been times when my faith has been questioned by people who don't know me. Where they said that I adhered to a different religion, as if that were somehow a bad thing.

Around the world we've seen intolerance and violence and terror, perpetrated by those who profess to be standing up for their faith but are in fact betraying it. No society is immune to the darkest impulses of man, and too often, religion has been used to tap into those darker impulses, as opposed to the light of god. Three years ago in our state of Wisconsin back in the United States, a man went into a Sikh temple and, in a terrible act of violence, killed six people, Americans and Indians. And in that moment of shared grief, our two countries reaffirmed a basic truth, as we must again today: that every person has the right to practise their faith how they choose, or to practise no faith at all, and to do so free of persecution and fear and discrimination.

The peace we seek in the world begins in human hearts, and will find its glorious expression when we look beyond any differences in religion or tribe and rejoice in the beauty of every soul. And nowhere is that more important than India. Nowhere is it going to be more necessary for that foundational value to be upheld. India will succeed so long as it is not splintered along lines of religious faith; so long as it is not splintered along any lines and is unified as one nation. And it's when all Indians, whatever your faith, go to the movies and applaud actors like Shah Rukh Khan, and when you celebrate athletes like Milkha Singh or Mary Kom, and every Indian can take pride in the courage of the humanitarian who liberates boys and girls from forced labour and exploitation. That's what unifies us.

empathy? Are we measured by our efforts, on what Dr [Martin Luther] King called the content of our character rather than the colour of our skin, or the manner in which we worship our god? In both our countries, in India and in America, our diversity is our strength and we have to guard against any efforts to divide ourselves along sectarian lines or any other lines. And if we do that well, if America shows itself as an example of diversity, of its capacity to live together and work together in common effort and common purpose, and India, as massive as it is with so much diversity, so many differences, is continuously able to affirm its democracy — that is an example for every other country on earth. That's what makes us world leaders. Not just the size of our economy or the number of weapons we have, but our ability to show the way in how we work together, how much respect we show each other. Sisters and brothers of India. We are not perfect countries, we have known tragedy and we have known triumph. We are home to glittering skyscrapers but also terrible poverty, new wealth but also rising inequality. We have many challenges in front of us. The reason I stand here today and I am so optimistic about our future together is that despite our imperfections, our two nations possess the keys to progress in the centuries ahead. We vote in free elections, we work and we build and we innovate and we lift up the least among us. We reach for heights previous generations could not even imagine. We respect human rights and human dignity, and it is recorded in our constitutions. We keep striving to live up to those ideals. We do these things because they make our lives better and safer and more prosperous, and we also do them because our moral imaginations extend beyond the limits of our lives. We believe that the circumstances of our birth need not dictate the arc of our lives. We are all beautiful flowers from the same garden, branches of the same majestic tree. +++

(Courtesy By - The India Express)

Dalit budgeting

(Cont...from page - 8)

not divisible, i.e. cannot be separated into schemes for SCs/STs and that for others. It is technically calculated at 16.2% shown under 789 minor heads. These technical figures are taken as allocation, without actual flow of funds for them. Sarva Shiksha Abhiyan and Health Mission have non-targeted (notional) allocation in which a big chunk of funds is allocated to SCSP and TSP but in reality no real funds flow for them because these schemes are for everybody. Besides, schemes are more in the nature of welfare rather than skill development, land purchase, entrepreneurship and creation of fixed assets, etc. Unless this money is benefiting directly to individuals, households and habitats of SCs/STs, schemes will remain eyewash. There are 43 ministries/ departments which have no obligation to earmark the funds for SCSP and TSP. In FY 2012-13, the targeted allocation was 6918.09 and notional 2292.23, and non-targeted allocation 12333.99. On an average, 70-75% fund utilized is non-targeted. If we critically examine then it shows that major expenditure incurs on survival of SCs/STs. The total amount under SCSP in 2013-14 was 41561.13, out of which 28261.57 is on survival, which comes to 68%, and on development it is 20%, participation 11%, protection 1%. In FY 2013-14, the planned budged was 555322, and allocation for SCSP was 41561. Hence, shortfall keeps on persisting in every budget.

Some of the States flagrantly violate the utilization norms and divert the funds to general schemes. In Odisha 40.51 was allocated for national highways and for other purposes like construction of jails, etc. In Delhi Commonwealth Games in 2010-11, Rs. 744 crore was utilized. In UP mostly money is spent on notional basis. For staff training at ITI Aliganj, Lucknow, 14.41 crore was utilized which has nothing to do with these schemes. The budget allocation made to the SCSP/TSP should be shown in minor heads of 789 separately in the budget documents. Currently, 20 departments have not opened even heads in Maharashtra, Madhya Pradesh, and Rajasthan. Some of States merely make arithmetic calculation to show population percentage plan expenditure under SCSP and TSP.

Schemes for Dalits and Tribals' development are not updated whereas situations have changed. The implementing agencies give hundred excuses and nodal officers are not normally designated. Even if there are nodal officers but they become handicapped when programmes are notional. There are no separate cells in the ministries which can plan, monitor and coordinate. In Ministry of HRD there is a team of forty experts to supervise Sarva Shiksha Abhiyan but why not for such gigantic plan? For implementation of SCSP/TSP there is more urgency to have monitoring cells at national, State and District levels comprising of experts and community people. The Hon'ble Finance Minister is going to present the budget and hope that this will be looked into. Andhra Pradesh was the first State to legalize SCSP/TSP which means that funds cannot be diverted. A stringent law is needed to punish those who divert and misutilize the funds.

How can the cause of nationalism espoused unless every section is included in the developments. Had there not been reservation and schemes to ameliorate Dalits and Tribals, they would have been languishing in every sphere, and where there are no safeguards, they are excluded everywhere like media, industry, share market, education, service sector, IT, construction, art and culture, exports and imports and markets, etc.

The writer is the Member of Parliament from North-West Delhi Constituency.

+++

Appeal to the Readers

You will be happy to know that the **Voice of Buddha** will now be published both in Hindi and English so that readers who cannot read in Hindi can make use of the English edition. I appeal to the readers to send their contribution through Bank draft in favour of **'Justice Publications'** at T-22**,** Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001. The contribution amount can also be transferred in 'Justice Publications' Punjab National Bank account no. 0636000102165381 branch Janpath, New Delhi, under intimation to us by email or telephone or by letter. Sometimes, it might happen that you don't receive the Voice of Buddha. In that case kindly write to us and also check up with the post office. As we are facing financial crisis to run it, you all are requested to send the contribution regularly.

Contribution:

Five years : Rs. 600/-

One year : Rs. 150/-

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 18 ● Issue 5 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● 16 to 31 January, 2015

DR. UDIT RAJ, AN OUTSTANDING SON OF INDIA

Rekha Vohra

It is the easiest thing in the world to be born with a golden spoon in one's mouth and then fall to the ground. It is very tough to rise from the bottom and make your mark in society, driven by nothing more than a burning desire to serve the underprivileged and down trodden.

We just celebrated birthday of Dr. Udit Raj, Member of Parliament from North-West Delhi. People from all walks of life came, not just those from the weaker socio-economic strata.

Born into a Dalit family in a remote village of Ram Nagar near Allahabad, he experienced the worst of India's centuries-old caste system. The more he was ostracized, the more deeply the fire for justice raged in his belly. He was determined to venture where angels feared to tread and he did.

He studied relentlessly and took the All India Civil Services Examination, qualifying for the Indian Revenue Service in his first attempt. He could have basked in the comfort of a secure Government job and retired at the top of the pyramid. But he was restless.

He tried to help his people, but was constrained by the rule-bound systems of the civil service. So, one morning, he upped and out. He never looked back. He set up a movement for India's scheduled castes and scheduled tribes. He wanted to give them hope and confidence, to restore their dignity.

Inspired by the teachings of Lord Buddha, he took the path of nonviolence and compassion. To the manner born, he lived a life of total simplicity. High thinking, humble living is his credo. And success has come to him in more ways than he could have imagined. He contested India's most recent general election in May 2014 and won a stunning victory. He is now a proud member of India's Parliament.

Dr. Udit Raj is hailed as a messiah. He disagrees. "I am but a servant of the wonderful people of India" he says, "my heart is with the weak and the exploited; my mind is with the great Indian family".

He follows a schedule that makes those much younger breathless. He sleeps less than four hours. He is always available for advice, for guidance, for support. His compassion is transparent. So is his impatience with delays and bureaucratic inertia.

He respects women and children. No human is too small or too insignificant, not to warrant his undivided attention.

People come to him day and night. His home resembles a village fair ground. Work is his worship. His transcendent energy is infectious.

He could have moved into the rarefied atmosphere of India's parliamentary enclave. He chose to stay with his people. He loves them and they return his affection in ample measure.

A senior Indian diplomat attended Udit Raj's birthday celebration on 27th January 2015. He listened to the accolades with rapt attention. And then he said: "Give me 1,000 clones of Dr. Udit Raj and we will transform India within a matter of days". Dr. Udit Raj is a symbol, an icon, a beacon for the future.

His vision for India is in sync with that of the country's Prime Minister. "We have to transform this ancient nation" he says quietly, before moving out to softly reassure a widow who has been hurt by the "system". She glows as he holds her hands. Her eyes fill with water; he gently wipes her tears and says: "Mother, your son is still alive". She breaks down. I put my kerchief to my own eyes.He celebrated his birthday as Justice Day. No one could disagree.More power to his elbow. He is singularly well-placed to strengthen the party that now rules India. +++

Mumbai felicitated Dr. Udit Raj on his B-Day

Dalit budgeting

Dr. Udit Raj

Reservation in the jobs and politics for Dalits is not a prime means to uplift them economically, rather it is a representation in the diverse society to keep strong bond of nationalism. It is also a mechanism to compensate the ancient wrongs. Success of largest democracy in the world owes a lot to the representation of varied sections of society unlike before independence. The SCs and STs constitute 25% of population in India and there have been policies to allocate resources proportionate to their population. The Central and State Governments are responsible to protect, promote and develop them at par with others. When the Government realized that despite many welfare schemes in the vogue, Dalits and Tribals have not been benefited from the Five Year plans as other communities, and under these circumstances, the Planning Commission introduced Tribal Sub Plan (TSP) in 1974-75 and Scheduled Caste Sub Plan (SCSP) in 1979-80 in Central and State Plans. The ideas behind these policies were to set apart annual budget of each Ministry and Department in proportion to their population. Not only Dalits and Tribals are being denied the share in budget allocation but whatever the funds are disbursed, are either diverted or unutilized, and in some cases, returned also.

The pattern of denial of allocation of funds under SCSP and TSP clearly reveals discriminatory attitude. In the past three Five Year Plans, i.e. 10th, 11th and last three financial years under 12th Five Year Plan of Union Budget, a huge amount has been curtailed. In 2002-03 total plan expenditure was 71569.41 crore and out of which only 305.73 was allocated for SCSP and TSP and whereas it should have been 17462.94. In 2003-04 the allocation was 249.75 against 19187.68 and 2004-05-06-07 denial amount is even larger. In 11th Five Year Plan, denial under SCSP in 2007-08 was 13307.80, 2008-09 was 15004.50 and the denial has increased in subsequent years. In 2013-14 the amount of denial was 26327.89.

Dalits and Tribals suffer not only on one count but several. Denial of their share in budgetary allocation is one aspect and the tragedy persists in the realm of utilization too. In 2012-13 the budgetary allocation under SCSP was 37113.03 and unutilized amount 3952.09. Discrimination is not only at the level of allocation, utilization but at implementation also. Allocation is more of nature of notional and general than targeted. The argument is that schemes in Ministries are

(Cont...on page 7)

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.

Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com

Computer typesetting by C. L. Maurya